Reports received from the State Government reveal a favourable impact on enrolment and attendance of children in primary classes in Uttar Pradesh.

Funds allocated to Uttar Pradesh under NLM

2955. SHRI AKHILESH DAS: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the details of the National Literacy Mission (NLM) project with its office location;

(b) the fund allocation to the State of Uttar Pradesh during the last two years, year-wise;

(c) the criteria of granting the fund to States;

(d) whether the fund allocated to Uttar Pradesh has been utilised.

(e) if so, the names of the districts, alongwith literacy mission programmes held and details of fund incurred in each of the district, as well as programmes in Uttar Pradesh; and

(f) the details of the amount to be sanctioned during the year 1997-98?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EDUCATION IN THE MINISTRY . OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MUHI RAM SAIKIA): (a) National Literacy Mission is one of the Five Technology Missions which is mandated to impart functional literacy to 100 million non-literates in 15—35 age group by 1999. NLM is an integral part of Ministry of Human Resource development, Department of Education located in Shastri Bhawan, New Delhi.

(b) and (c) Under the Total Literacy Campaigns funds are not allotted to States. Funds are released directly to the Zila Saksharata Samitis (ZSSs), registered societies at the District Level.

The project for literacy campaigns as submitted by ZSSs and recommended by the State Government are aproved by the Project Approval Committee of National Literacy Mission. The Expenditure on the Campaign is shared by the Central and State Governments in the ratio of 2:1. In Tribal districts the corresponding cost sharing ratio is 4:1.

(d) and (e) The names of the districts alongwith the amounts sanctioned in 1995-96 and 1996-97 is given in the enclosed Statement *(See* below). The sanctioned fudns are being utilised by the Zila Saksharata Samitis for implementation of literacy campaigns which are in various stages of progress.

(f) No prior State-wise allocations are made under the scheme of Total Literacy Campaigns.

Statement

Funds allocated to Uttar Pradesh

(Amount Sanctioned in Rs.)

S.No.	District (ZSS)	1995-96	1996-97
1.	Allahabad	20,00,000	
2.	Rampur	1,00,00,000	
3.	Muzafarnagar	50,00,000	
4.	Ferozabad	25,00,000	
5.	Meerut	25,00,000	
6.	Allahabad	3,32,00,000	
7.	Sitapur	2,16,00,000	
8.	Padrauna	71,58,000	

S.No.	District (ZSS)	1995-96	1996-97
9.	Gorakhpur	40,00,000	
10.	Banda	1,48,65,000	
11.	Lucknow	1,15,87,000	
12.	Bhadoi	40,00,000	
13.	Ghaziabad	13,64,000	
14.	Etah	30,00,000	
15.	Aligarh	1,39,20,000	
16.	Saharanpur	10,00,000	64,17,000
17.	Balia		40,00,000
18.	Pauri Garwal		20,00,000
19.	Sonbhadra		43,00,000
20.	Nainital		18,00,000
21.	Udham Singh Nagar		43,50,000
22.	Haridwar		47,80,000
23.	Ambedkar Nagar		15,00,000
24.	Varanasi		51,00,000
25.	Bulandshahar		23,18,000

उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की परियोजनाएं

2956. श्रीमती मालती शर्मा: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कौन-कौन सी परियोजनाओं को कार्यान्वित किया गया था और अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विचार के लिये अग्रेषित किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय महिला कोष को आवंटित धनराशि

2957. श्री दिलीप सिंह जूदेव: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1995-96 के दौरान राष्ट्रीय महिला कोष को कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) क्या संपूर्ण धनराशि देश में जरूरतमंद महिलाओं को उपलब्ध करा दी गई है; तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जरूरतमन्द महिलाओं को ऐसी सहायता गैर-सरकारी संगठनों द्वारा भी उपलब्ध कराई जाती है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं, और

(ङ) क्या कोष से सहायता प्राप्त करने के लिए पंजीकृत संगठन का होना अनिवार्य है, यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस० आर० बोम्मई): (क) राष्ट्रीय महिला कोष के लिए वर्ष 1995-96 के बजट में एक लाख रुपये का सांकेतिक प्रावधान किया गया था। तथापि, कोष को कोरपस निधि प्रदान की गयी है, जिसमें वर्ष 1995-96 में 42 करोड़ रुपये का राशि उपलब्ध थी।

(ख) वर्ष 1995-96 में, 37,502 महिलाओं को ऋण प्रदान करने के लिए 48 गैर-सरकारी संगठनों को 861 लाख रुपये ऋण स्वीकृत किया गया। इस अवधि में, मुख्य स्कीम के अन्तर्गत 534.126 लाख रुपये वितरित किये गए, जिससे लगभग 24.270 महिलाए लाभान्वित हुई।

(ग) इस विभाग के पास इस आशय की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है कि जरूरतमंद महिलाओं को अन्य गैर-सरकारी संगठनों द्वारा भी इस प्रकार की